nt>
Title: Requests the Central Government to inform the House regarding the lifting of economic sanctions by the various countries.

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान परमाणु परीक्षण के बाद पैदा हुई स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं। उसके बाद अमेरिका से २-३ बार बात हो चुकी है लेकिन श्री जसवंत सिंह जी को दो बार अमरीका भेजा जा चुका है और अब तीसरी बार की चर्चा हो रही है। वे क्या बोल रहे हैं, यह देश के सामने नहीं आ रहा है। अब सोमवार को चौथी बार जाने की बात हो रही है। इससे देश को और यहां रहने वाले सभी लोगों के मन में इस बात की शंका हो रही है कि क्या बात चल रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सोमवार को चौथी बार जाने से पहले इस सदन को बता दिया जाये कि क्या बात चल रही है। क्या सैंक्शन्स उठाये गये हैं या नहीं? इसके अलावा और क्या बातें होनी हैं? क्या अमरीकी प्रेज़ीडेंट द्वारा उनके कान में विशेष बात कही गई है ? अभी पाकिस्तान और भारत के दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत श्रीलंका में होने वाली है, इसके लिये अमरीकी सैक्रेट्री ऑफ स्टेट द्वारा कान में मंत्र फूंका गया है, वह इस सदन के सामने लाया जाये ताकि सदस्यों के मन में कोई दुराग्रह न रहे।

">SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, the sanctions against India from various countries are causing a lot of problems in our economic sphere. The Government has been expressing that, on many counts, they will be overcoming them. It is a good sign that the Americans - the Senators, the Congressmen and the people of that country - at least now are thinking on that line. Even the Glenn Amendment, which was standing against the lifting of sanctions or, for that matter, for any kind of mitigating of the sanctions has also to be changed at this stage. Now, they are thinking on that line. So, at this stage, the talks between India and the US and also the talks between India and the other countries with regard to the lifting of the sanctions as well as the matters concerning our boundaries are of great importance.

So, I would also support Shri Shinde and urge upon the Government to leave this matter, make these matters more clear and to take up the matter with more seriousness so far as the interests, the security and the economic situation of this country are concerned.